

NT>

**12.02 hrs.**

Title: Regarding recent visit of Shri Vladimir Putin, President of the Russian Federation to India.

**प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी)** : अध्यक्ष महोदय, रूसी संघ के राष्ट्रपति 3 से 5 दिसम्बर तक राजकीय दौरे पर भारत आए थे। उनकी इस यात्रा ने हर वा शिखर बैठकें आयोजित करने की उस नई परम्परा को कायम रखा है जिस की हमने अक्टूबर, 2000 से शुरुआत की थी। राष्ट्रपति पुतिन हमारे राष्ट्रपति जी से मिले, जिन्होंने गणमान्य अतिथि के सम्मान में प्रीतिभोज दिया। उप राष्ट्रपति, उप प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और लोक सभा में विपक्ष की नेता ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की।

राष्ट्रपति पुतिन और मैंने द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक बातचीत की और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इस विचार-विमर्श से भारत एवं रूस के पारस्परिक हितों के अनेक मुद्दों पर हमारी गहन सहमति मुखरित हुई है।

इस यात्रा के समापन पर जो महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए गए, वे हमारे अनेकानेक हितों को परिलक्षित करते हैं। इनमें स्ट्रेटेजिक भागीदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाने संबंधी दिल्ली घोषणा-पत्र, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय सहयोग को मजबूत करने हेतु एक संयुक्त घोषणा-पत्र तथा आतंकवाद से निपटने में सहयोग करने संबंधी एक समझौता-ज्ञापन शामिल हैं। ये दस्तावेज तथा इस यात्रा से संबंधित संयुक्त वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिए गए हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए गए। कर्नाटक सरकार तथा रूसी संघ के समारा क्षेत्र के बीच सहयोग संबंधी एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए गए।

हम समझते हैं कि इन दस्तावेजों से भारत और रूसी संघ के बीच बहु-आयामी सहयोग के राजनैतिक-कानूनी आधार को और मजबूती मिलेगी।

राष्ट्रपति पुतिन और मैं इस बात पर सहमत हुए कि हमारे दोनों देशों को अपने व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कोई नई पहल करनी चाहिए। हमें अधिक मूल्य एवं उच्च तकनीक वाली वस्तुओं तथा तेल एवं गैस, हीरा आदि जैसे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाना होगा। हमें व्यापार के क्षेत्र में विविधता लाने की तत्काल जरूरत है क्योंकि रुपए और रूबल के संबंध में हमारे द्विपक्षीय समझौते के तहत ऋण भुगतान की मात्रा में वर्ष 2005 से तेजी से गिरावट आ रही है। इस समय भारत से रूस को किया जाने वाला लगभग समस्त निर्यात इसी ऋण भुगतान द्वारा पोषित होता है। हम आपसी निवेश बढ़ाने की जरूरत पर भी सहमत हुए।

ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हमारे दोनों देशों के लिए दीर्घकालीन स्ट्रेटेजिक महत्व रखता है। दोनों पक्ष विश्व ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करती है, पर समुचित व्यवस्था के तहत नियमित रूप से द्विपक्षीय विचार-विमर्श करेंगे। सखालिन-1 परियोजना में हमारे सहयोग में अच्छी प्रगति हुई है। हम कैस्पियन सागर सहित अन्य क्षेत्रों की परियोजनाओं में तथा ऊर्जा क्षेत्र के दूसरे पहलुओं पर अपने सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।

कुदुनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर हमने संतोष व्यक्त किया और यह महसूस किया कि इस क्षेत्र में और अधिक सहयोग दोनों देशों के हित में होगा। राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु ऊर्जा को असैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाने के संबंध में भारत के साथ सहयोग को जारी रखने में रूस की दिलचस्पी की पुष्टि की। हमारी बातचीत के बाद, संयुक्त प्रेस सम्मेलन में उन्होंने विचार व्यक्त किया कि इन मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है। हम इस बात पर पूरी तरह से सहमत हैं।

माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि भारत और रूस के बीच रक्षा के क्षेत्र में व्यापक सहयोग है। अब हमारा सहयोग केवल हथियारों के क्रेता और विक्रेता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संयुक्त रूप से अनुसंधान, विकास और उत्पादन भी शामिल है। अत्याधुनिक ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र हमारे संयुक्त अनुसंधान और विकास प्रयासों का परिणाम है। भारत और रूस दोनों ही इस प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का संयुक्त उत्पादन शुरू करने जा रहे हैं ताकि इसे दोनों देशों के सशस्त्र बलों में शामिल किया जा सके। राष्ट्रपति पुतिन और मैं इस बात पर सहमत थे कि ऐसी कई अन्य परियोजनाएं हैं जिनमें हम भविष्य में सहयोग कर सकते हैं।

दिल्ली घोषणा-पत्र में इस सिद्धान्त पर बल दिया गया है कि हम दोनों में से कोई सा भी देश ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे दूसरे देश की सुरक्षा पर कोई आंच आए। हमने यह घोषणा की है कि दोनों देश अपनी सुरक्षा तथा रक्षा नीतियों में और तीसरे देशों के साथ सैन्य-तकनीकी सहयोग करते समय इन सिद्धान्तों का पालन करेंगे। ये महत्वपूर्ण आपसी वचनबद्धताएं हैं जो भारत और रूस के बीच सक्रिय रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की समीक्षा करते समय हमारा यह समान मत था कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ठोस और स्थायी उपाय किए जाने चाहिए। आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों - और विशेषकर प्रस्ताव संख्या 1373 - का कड़ाई से पालन किया जाए। भारत और रूस दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित हैं और आतंकवाद की जड़ें हमारे दोनों देशों के पड़ोस में फैली हुई हैं, इसलिए भारत और रूस का ठोस सुरक्षा हित इसी में निहित है कि इस खतरे का मुकाबला राष्ट्रीय और द्विपक्षीय स्तर पर निवारक और निरोधक उपायों के जरिये किया जाए। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त कार्य दल गठित करने संबंधी आपसी समझौते से इस क्षेत्र में हमारा सहयोग और अधिक सुदृढ़ होगा।

भारत और रूस ने अलकायदा और तालिबान ताकतों, जिनका उनके प्रायोजकों से बराबर संपर्क बना हुआ है, के फिर से एकजुट होने से अफगानिस्तान की सुरक्षा को जो खतरा बना हुआ है, उस पर भी गंभीर चिंता जाहिर की। हमने राष्ट्रपति करजाई की सरकार का, तथा राष्ट्रीय मेल-मिलाप, आर्थिक पुनर्स्थापना और अफगानी संस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए उसके द्वारा किए जा रहे प्रयासों का, पूर्ण समर्थन किया। भारत और रूस अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने में सहयोग करेंगे। इनमें अफगानिस्तान की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जायेगा। अफगानिस्तानी नेतृत्व के साथ भारत अपनी द्विपक्षीय बातचीत भी जारी रखेगा तथा अफगानिस्तान की जनता के साथ अपने पारस्परिक संबंधों को और सुदृढ़ बनाएगा।

दक्षिण-एशिया की स्थिति पर हमारे दृष्टिकोणों की समरसता को हमारे संयुक्त वक्तव्य में दर्शाया गया है। रूस हमारे इस रुख से सहमत है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी शुरू कर सकते हैं जब वह सीमा पार से घुसपैठ रोके और पाकिस्तान तथा पाक-नियंत्रित क्षेत्र में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करे।

संक्षेप में, राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा से भारत और रूस के आपसी हितों से जुड़े सभी मुद्दों पर हमारी शिखर स्तरीय बातचीत को जारी रखने का महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा हुआ है। इस यात्रा से हमारी इस आपसी प्रतिबद्धता को बल मिला है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक भागीदारी को निरंतर सुदृढ़ बनाएं, अपने राजनैतिक विचार-विमर्शों में तेजी लाएं और अपने आर्थिक संबंधों को नया स्वरूप प्रदान करें। इस यात्रा से प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारे समान दृष्टिकोण की पुष्टि हुई है।

हम रूस के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च महत्व देते रहेंगे। वाकि शिखर बैठकें आयोजित करने की हमारी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए मैंने अगले वर्ष रूस की यात्रा करने के राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है।